स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

वर्ष - 13 अंक - 314 | कल्याण (मुंबई), 1 से 15 जून 2015 | पेज-8 | मूल्य 5 रु.

रेलवे ट्रैक पर आंदोलनों पर कठोरता से नियंत्रण करें -सिन्हा

दिल्ली : रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में 21 मई को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर रेलवे के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की. इस अवसर पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. पुठिया, अपर महाप्रबंधक एस. के. पाठक तथा सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे. बैठक में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों में सलाहकार/जन परिवाद आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक/नवीकरण मधुकर सिंह, रेल राज्यमंत्री के निजी सलाहकार नीतेश्वर कुमार उपस्थित थे. महाप्रबंधक/उ.रे. श्री पुठिया एवं उनके विभाग

प्रमुखों द्वारा विभिन्न मानकों पर आधारित पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ विभागवार कार्य-निष्पादन प्रस्तुत किया गया. बड़े मुद्दों और समस्याओं पर विचार-विमर्श के साथ चालू वर्ष की कार्य-योजना पर चर्चा भी की गई.

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उत्तर रेलवे के

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने की उत्तर रेलवे की कार्य-निष्पादन समीक्षा

कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना की. श्री सिन्हा ने समय-पालन कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर आंदोलन और प्रदर्शनों पर समय से नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन के साथ सम्पर्क बनाया जाए. उन्होंने अलार्म चेन खींचने तथा गाड़ियों के समयपालन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कमी लाने के निर्देश दिए.

श्री सिन्हा ने अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वालों की संख्या में आने वाली कमी पर चिंता प्रकट की. उन्होंने निर्देश दिया कि कुछ विशेष रेल सेक्शनों पर टिकट जाँच को बढ़ाकर और मामले की जाँच करके केन्द्रीकृत उपाय किए जाएं. परिसम्पत्तियों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जोन द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि शेष पेज 8 पर...

रेल उपभोक्ता पखवाड़ा

मोदी सरकार का एक और अभियान

दिल्ली : केंद्र में मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर 'स्वच्छ भारत अभियान' की तर्ज पर रेल यात्रियों से सीधा संवाद कायम करने के लिए रेलवे ने 26 मई से 'रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े' का आयोजन किया गया है. इस दौरान रेलवे बोर्ड, जोनल एवं मंडल अधिकारी करीब 8000 स्टेशनों पर पहुंच कर यात्रियों से बातचीत करेंगे और रेल बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन, स्टेशनों पर यात्रियों को होने वाली परेशानियों और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान रेलवे देश भर में कुल मिलकर करीब सौ रेल परियोजनाओं की शुरूआत भी का जा रही है. रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार, 25 मई को रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए. के. मित्तल के साथ सभी जोनों एवं रेलवे उत्पादन इकाईयों के महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके इस पखवाड़े की तैयारियों को अंतिम रूप दिया.

इस पखवाड़े के लिए रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रणाली) मोहम्मद जमशेद को इस पूरे अभियान का संयोजक बनाया गया है. रेलवे बोर्ड से लेकर जोनल एवं मंडल कार्यालयों तक शेष पेज 7 पर...

देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट भारतीय रेल को तोड़ने वाला दस्तावेज है -एआईआरएफ

दिल्ली : ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) की स्थाई समिति की दिल्ली में 22-23 मई को हुई दो दिवसीय बैठक में अर्थशास्त्री डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय रेलवे पुनर्गठन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार से

वर्तमान सरकार कॉर्पोरेट घरानों को ट्रेन सेवाएं चलाने और रेल यात्रियों से हवाई टिकटों जैसे रेल किराए वसूलने की अनुमति देकर सिर्फ बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही वर्तमान रेलवे व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही है – एआईआरएफ

चर्चा की गई. बैठक में इस बात पर सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है कि डॉ. देबरॉय की यह अंतरिम रिपोर्ट भारतीय रेल व्यवस्था को शेष पेज 7 पर...

एनएफआईआर ने देबरॉय समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी के हवाले किया

डॉ. एम. राघवैया, महामंत्री, एनएफआईआर

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया ने 34 पेज के अपने विश्लेषण में अर्थशास्त्री और 'नीति-आयोग' के उपाध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय रेलवे पुनर्गठन समिति की करीब सवा तीन सौ पेज की अंतरिम रिपोर्ट को रद्दी का पुलिंदा बताते हुए उसे कचरा पेटी के हवाले कर दिया है. डॉ. राघवैया ने यह 34 पेज का विश्लेषण डॉ. बिबेक देबरॉय को भेजकर कहा है कि बिना पहले आवश्यक रेलवे ढ़ांचा तैयार किए विदेशी (एफडीआई) और निजी निवेशकों (पीपीपी) को भारतीय रेल के वर्तमान ढ़ांचे पर खेलने अथवा इसका दोहन करने (मुनाफा कमाने) की अनुमति नहीं दी जा सकती है. डॉ. राघवैया ने एफडीआई, पीपीपी, रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन और रेलवे बोर्ड को तोड़ने अथवा पुनर्गठित किए जाने सहित देबरॉय समिति की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से नकार दिया है.

शेष पेज 7 पर...

अंतिम निष्कर्ष....

1. देबरॉय समिति पूर्व की केंद्र सरकारों द्वारा रेलवे में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा नहीं दिए जाने के कारणों का परीक्षण करने में फेल रही है, जबकि गलत धारणा के तहत इसके लिए रेलवे की वर्क फोर्स को जिम्मेदार ठहराया है.
2. पहले पर्याप्त रूप से विकसित रेलवे ढ़ांचा तैयार किए बिना विदेशी और निजी निवेशकों को वर्तमान ढ़ांचे के दोहन की अनुमति नहीं दी जा सकती.
3. रोड-मैप के उत्साह में देबरॉय समिति ब्रिटिश रेलवे के निजीकरण के फेल हो गए मॉडल सहित यूरोपियन रेलों की समस्याओं का अध्ययन करने में सक्षम नहीं रही है.
4. एक टेबल में देबरॉय समिति ने परभणी को दक्षिण मध्य रेलवे का डिवीजन बताया है, जो कि वास्तव कहीं नहीं है, इससे यह पता चलता है कि समिति ने अत्यंत जल्दबाजी में रेलवे बोर्ड से इनपुट्स लिए हैं.
5. भविष्य और वर्तमान की जरूरतों पर योजनाबद्ध ढ़ंग से विचार-विमर्श किए बिना रिस्ट्रक्चरिंग की कसरत ऐसे दिग्भ्रमित एवं उलझनपूर्ण तरीके से नहीं की जा सकती है.

पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में 'यात्री सुविधा पखवाड़ा'

कोलकाता : पूर्व रेलवे नियमित यात्रियों और लंबी दूरी की ट्रेन के यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार, 26 मई से 'यात्री एवं ग्राहक सुविधा पखवाड़ा' मना रहा है. पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक आर. के. गुप्?ता ने कहा कि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का खुद से अनुभव करने के लिए मैं और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग ट्रेनों में सफर करेंगे और यात्रियों से बात कर जानेंगे कि रेल यात्रा के दौरान क्या वह किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं. श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसी योजना बनाई गई है कि मैं, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी पखवाड़े के दौरान पूर्वी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्टेशनों पर यात्रियों से सीधे बातचीत करेंगे.

श्री गुप्?ता ने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने कहा कि पूर्व रेलवे द्वारा सर्वप्रथम वंचित लोगों के फायदे के लिए दूरदराज के इलाकों में अपने डॉक्टरों से स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की हालत को लेकर काफी गंभीर हैं. श्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बाद अब रेल मंत्रालय रेलवे में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर काफी गंभीर नजर आने लगा है. इसके लिए रेल मंत्रालय ने सभी जोनों में यात्री पखवाड़ा चलाकर अधिकारियों को यात्रियों तक पहुंचने का आदेश दिया है.

इसके तहत पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने 26 मई से शुरु हुए यात्री पखवाड़े की सफल बनाने की पूरी तैयारी की है. यात्री और उपभोक्ताओं के पास पहुंचकर सुविधाओं के बाबत जानने और रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को उन तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया है. इस दरम्यान रेल अधिकारी ट्रेनों और प्लेटफार्मों में पहुंचकर यात्रियों से रेलवे द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेंगे. द.पू.रे. के चारों मंडलों खड़गपुर, आद्रा, रांची और चक्रधरपुर तथा पू. रे. के हावड़ा, सियालदह, मालदा और आसनसोल मंडलों में 26 मई से शुरू हुए यात्री पखवाड़े पर दोनों महाप्रबंधकों - राधेश्याम और आर. के. गुप्ता - द्वारा सीधे नजर रखी जा रही है. इसके अलावा दोनों महाप्रबंधक खुद भी यात्रियों से रूबरू होकर उनकी सुविधाओं या परेशानियों की बाबत जानकारी हासिल करेंगे. सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए उनकी राय भी लेंगे.

द.पू.रे. के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी संजय घोष ने बताया कि पखवाड़े के दौरान खासतौर पर यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके अलावा लोगों/यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी मंडलों में रेल अधिकारी यात्रियों के लगातार सम्पर्क में बने हुए हैं. यात्री जागरूकता के लिए बैनर भी लगाए गए हैं. पखवाड़े को सफल बनाने के लिए सभी उपयुक्त तैयारियां की गई हैं.

इस यात्री पखवाड़े में यात्रियों से वर्तमान में रेलवे की व्यस्थाएं कैसी हैं? स्टेशन, ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई से वे कितना संतुष्ट हैं और क्या बदलाव होने चाहिए? आदि प्रकार के सवाल रेल अधिकारियों द्वारा पूछे जा रहे हैं. यात्रियों से मिले फीडबैक और सुझाव को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. रेलवे की वर्तमान व्यवस्थाओं, कमियों और जरूरी बदलाव के लिए रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की राय जानने के निर्देश दिए हैं. पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भी 26 मई से 9 जून तक इस संबंध में अभियान चलाया जा रहा है. इसमें ऐसी ट्रेनों को चुना गया है, जिनमें ज्यादा भीड़ और अव्यवस्थाएं होती हैं.

भारतीय रेल देश के परिवहन की रीढ़ है -राजीव मिश्र

गोरखपुर : संरक्षित एवं सुरक्षित रेल यात्रा सुनिष्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र की अध्यक्षता में 'रेल गाड़ियों में आग से रोकथाम' विषय पर संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन 16 मई को रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर में किया गया. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके संरक्षा संगोष्ठी का शुभारम्भ किया. महाप्रबंधक ने इस अवसर पर ट्रेनों में आग से रोकथाम पर कम्पेंडियम तथा लोको पायलट्स के लिए इलेक्ट्रिक गाइड का विमोचन भी किया. संगोष्ठी में सभी विभाग प्रमुखों सहित मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के वरिष्ठ रेल अधिकारी तथा संरक्षा से जुड़े कर्मचारी उपस्थित थे.

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि भारतीय रेल देश के परिवहन की रीढ़ है. हमारा कर्तव्य है कि हम यात्रियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि चलती ट्रेनों में आग की रोकथाम एक गंभीर मुद्दा है. ट्रेन अग्निकांड मानव जीवन एवं सरकारी सम्पत्ति दोनों के लिए गंभीर आपदा है. महाप्रबंधक ने कहा कि ट्रेनों एवं स्टेशनों पर आग से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. फिर भी जांच प्रणाली की विफलता अथवा असामाजिक तत्वों के कार्य-कलापों से ट्रेनों में आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेन में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, यथा- विद्युत के शार्ट सर्किट, ट्रेन में ज्वलनषील पदार्थ - डीजल, पेट्रोल, गैस, स्टोव, विस्फोटक सामग्री का ले जाया जाना अथवा यात्रियों द्वारा धुम्रपान धूम्रपान करना. हम इन पर रोक लगाकर काफी हद तक ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को रोक सकते हैं.

महाप्रबंधक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे ट्रेनों में आग की रोकथाम हेतु अग्नि निवारण प्रबंधन के लिए सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में ऑन बोर्ड रोलिंग स्टाक एवं फायर डिटेक्शन के सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष निगरानी रखें. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि भारतीय रेल द्वारा ट्रेन अग्निकांड की रोकथाम हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं. भारतीय रेल कोचों को फायर प्रूफ बनाने हेतु प्रयासरत है. इसके अतिरिक्त सभी कोचों की आवधिक ओवरहालिंग के समय फायर प्रूफ सामग्री लगाई जा रही है. सभी वातानुकूलित कोचों, पैंट्रीकार, लोकोमोटिव एवं ब्रेकवान में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं. पैंट्रीकार में विद्युत एवं एलपीजी फिटिंग्स की आवधिक जांच की जा रही है. स्टेशनों पर अग्निशामक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. अग्रिम पंक्ति के रेलकर्मियों को आग बुझाने एवं अग्निशामक उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जा रहा है. महाप्रबंधक ने बताया कि ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में ज्वलनशील सामग्रियों को लाने एवं ले-जाने के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है तथा लोगों को संरक्षा के प्रति शेष पेज 3 पर...

सुरक्षित, संरक्षित एवं तीव्र गति से रेल संचालन का दायित्व हम सभी पर है -ओ.पी.अग्रवाल

गोरखपुर : रेल सप्ताह समारोह के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग का पुरस्कार वितरण समारोह 14 मई को रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर में आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि ओ. पी. अग्रवाल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, ने मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के इंजीनियरिंग विभाग के 200 रेलकर्मियों को प्रशस्ति-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया. इस अवसर पर एस. वी. सिंह, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, एन. एस. कुटियाल, मुख्य पुल इंजीनियर, एस. के. मिश्रा, मुख्य प्लानिंग एवं डिजाइन इंजीनियर, डी. के. सिंह, मुख्य इंजीनियर/सामान्य, एस. सी. श्रीवास्तव, मुख्य इंजीनियर/टीएमसी सहित मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए प्रमुख मुख्य इंजीनियर ओ. पी. अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षित, संरक्षित एवं तीव्र गति से रेल संचालन का दायित्व हम सभी पर है. उन्होंने कहा कि आप सभी अपने कार्यों को पूरी तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ निष्पादित करें, जिससे दुर्घटना रहित रेल संचालन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके. श्री अग्रवाल ने कहा कि हमें बीते वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा कर भविष्य में बेहतर रेल संचालन की योजना पर कार्य करना होगा. प्रमुख मुख्य इंजीनियर ने कहा कि पुरस्कार की सीमा निर्धारित होने के कारण सभी को पुरस्कृत नहीं किया गया है, फिर भी पुरस्कृत कर्मचारी अन्य के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे. सामूहिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ ब्रिज एवं सर्वश्रेष्ठ टैक की शील्ड लखनऊ मंडल को दी गई है. इसके अतिरिक्त विभिन्न इकाईयों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार दिया गया. पी. के. सिंह, सचिव/प्रमुख मुख्य इंजीनियर ने कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया.

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जारी किया गया हेल्प लाइन नं.

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाकर रेल यात्रियों को पारदर्शी एवं बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं. रेल उपयोगकर्ताओं के सीधे सम्पर्क में आने वाले सभी क्षेत्रों में कदाचार एवं दलालों की गतिविधियों को रोकने तथा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से सतर्कता संगठन अत्यन्त प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहा है. इन प्रयासों तथा उनसे प्राप्त परिणामों से समय-समय पर जनसामान्य को अवगत कराया जाता है, जिससे रेल यात्रियों की रेल की कार्यप्रणाली के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे तथा वे भी रेल में भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को रेलवे के संज्ञान में लाकर व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया में सहभागी बनें. इसी प्रयोजन से रेल प्रशासन द्वारा सतर्कता मोबाइल हेल्प लाइन संख्या 0551-155210 उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से किसी प्रकार के रेल सम्बंधी भ्रष्टाचार की सूचना सतर्कता संगठन को दी जा सकती है. सतर्कता संगठन आम नागरिकों से अपेक्षा करता है कि भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य यथा-विडियो, फोटोग्राफ, रिकार्डेड वायस अथवा अधिकृत दस्तावेज सीधे सतर्कता संगठन को भेजकर दोशी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके.

आरपीएफ ने यात्रियों का सामान चुराने वाले चोर को पकड़ा

भुसावल : चलती गाड़ी से यात्रियों का सामान चुराने वाले एक चोर को भुसावल आरपीएफ की गश्ती पार्टी ने पकड़ा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 एमी को गाड़ी नंबर 11057 पठानकोट एक्स. में नासिक रोड से भुसावल के दरम्यान गश्ती पार्टी ने गाड़ी के कोच नंबर एस-8 में संदिग्ध अवस्था में एक आदमी हो बैठे देखा. पूछताछ में उसने अपना नाम शेख वाहिद शेख अनीस, निवासी कुसुम्बा रोड, बस स्टैंड के पास, मालेगांव, जिला नासिक बताया. उसके सामान की तलाशी लेने पर उसमें से दो महंगे मोबाइल, उनके चार्जर, एक लेडीज पर्स, जिसमें एक जोड़ी कान के झुमके, दो जनाना अंगूठियां और आठ हजार रुपए नकदी सहित कुल करीब 50 हजार का माल बरामद हुआ. पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि एक चलती गाड़ी से एक महिला का उक्त सामान उसने चुराया था और अब उसको बेचने जा रहा था. आरपीएफ गश्ती पार्टी ने आगे की जांच और कार्रवाई के लिए भुसावल में उसे जीआरपी के हवाले कर दिया.

आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, गोरखपुर में हंगामा है क्यों बरपा ?

कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल के बीच जाति विशेष को लेकर गाली-गलौज, पोस्टरबाजी

विजयशंकर, ब्यूरो प्रमुख/एनईआर

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे के कतिपय कर्मचारीगण कामचोरी, चापलूसी और चरित्रहनन के लिए हमेशा से बदनाम रहे हैं. उनका सबसे पसंदीदा शगल दूसरों के खिलाफ चोरी-चुपके पोस्टरबाजी के माध्यम से सम्बंधित अधिकारी या कर्मचारी का चरित्रहनन करके उसे बदनाम करने का रहा है. पूर्वोत्तर रेलवे में, खासतौर पर गोरखपुर मुख्यालय परिक्षेत्र के दायरे में, अपने विरोधियों के खिलाफ पोस्टरबाजी के माध्यम से चरित्रहनन की ऐसी कई घटनाएं अब तक उजागर हो चुकी हैं. इन घटनाओं से न सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे की बदनामी हुई है, बल्कि सम्बंधित कर्मचारियों के बीच कई बार भारी तनाव भी व्याप्त हो चुका है.

ऐसी एक घटना हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र (आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर) गोरखपुर में दो कांस्टेबलों के बीच हुए गाली-गलौज के बाद पुनः घटित हुई है. इससे पहले इसी आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के एक प्रशिक्षु कांस्टेबल की अचानक मौत के बाद एक श्रमिक नेता को आरपीएफ के ही एक सहायक कमांडेंट द्वारा फर्जी मामले में फंसाने का मामला उजागर हो चुका है. प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार हाल ही में आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनर कांस्टेबल सी. के. सिंह और हेड कांस्टेबल सुनीत कुमार श्रीवास्तव के बीच किसी मामले में काफी कहासुनी हो गई. इस पर बताते हैं कि सी. के. सिंह ने सुनीत कुमार श्रीवास्तव को न सिर्फ मां-बहन की गालियों से नवाजा, बल्कि उनके माध्यम से उनकी पूरी लाला बिरादरी को भी गालियां दीं.

बताते हैं कि जब सिर्फ गालियां देने से ही सी. के. सिंह का मन नहीं भरा, तो उन्होंने एक ईंट उठाकर सुनीत कुमार श्रीवास्तव पर फेंक मारी. वह तो अच्छा हुआ कि उक्त ईंट श्रीवास्तव को नहीं लगी, वरना उनका सिर फूटना निश्चित था. बताते हैं कि इसके बाद अगली रात को ही पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय परिसर और इमारतों में लाला बिरादरी के खिलाफ गाली-गलौज वाली भाषा में लिखित एक पोस्टर चिपका दिया गया. इस पोस्टर (पम्फलेट) में सीएससी कार्यालय में कार्यरत एक अन्य लाला बिरादरी के मिनिस्टीरियल स्टाफ सहित सुनीत कुमार श्रीवास्तव और पूरी लाला बिरादरी को निशाना बनाया गया तथा उसके खिलाफ भारी अभद्र एवं अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है.

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि यह आपत्तिजनक पम्फ्लेट लगाने या लगवाने पर शक की सुई कांस्टेबल सी. के. सिंह की तरफ इशारा कर रही है? परंतु जब इस मामले में आरपीएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच (सीआईबी) ने कोई कदम नहीं उठाया, तब सिविल पुलिस में इसकी सूचना दर्ज की गई कि किसी आपत्तिजनक पोस्टरबाजी के चलते रेलवे परिसर में सामुदायिक तनाव फैला हुआ है. सिविल पुलिस ने इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इस संबंध में महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को एक लिखित सूचना भेजी है और उनसे संबंधितों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है.

सिविल पुलिस के थाना कैंट, जनपद गोरखपुर, के थाना प्रभारी ने रेलवे में दो वर्गों के मध्य तनाव और कसीदगी व्याप्त होने में निराकरण की कार्यवाही की सूचना देते हुए महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को लिखा है कि 'थाना स्थानीय के हॉक दस्ते के कर्मचारीगण द्वारा जी. डी. नं. 14, समय 9.15 पर बीट सूचना अंकित कराई गई है कि रेलवे परिसर स्थित भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कुछ आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए गए हैं. आम जनमानस एवं रेलवे कर्मचारीगण में चर्चा है कि आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में कुछ दिन पहले लाला जाति को गाली-गलौज देने के क्रम में उक्त घटनाएं हो रही हैं, जिससे लाला जाति के लोगों में

उत्तेजना है तथा उक्त घटना कभी-भी सामुदायिक संघर्ष में बदल सकती है.'

कैंट थाना प्रभारी ने आगे लिखा है कि 'उल्लेखनीय है कि इतनी संवेदनशील घटना का कतिपय रेलवे अधिकारीगण द्वारा समय से न तो संज्ञान लिया गया, और न ही पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया. इससे रेलवे के इंटेलिजेंस, विजिलेंस की उदासीनता परिलक्षित होने का पर्याप्त कारण बनता है. ऐसे तनाव और झगड़े निश्चित रूप से बड़े सामुदायिक संघर्ष का कारण बनकर कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं तथा पुलिस प्रशासन को असहजता का सामना करना पड़ता है और जनता को काफी कठिनाई होती है. पुलिस द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई करने में रेलवे प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप की संभावना होती है. अतः उक्त सूचना को आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लेते हुए समय से सूचना न देने वाले संगठनों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में कानून-व्यवस्था हेतु कोई नकारात्मक घटनाएं न होने पावें.'

कैंट थाना प्रभारी ने महाप्रबंधक को उपरोक्त रिपोर्ट प्रेषित करते हुए इसकी प्रतियां एसएसपी, गोरखपुर सहित पुलिस अधीक्षक नगर, गोरखपुर और सीएससी/आरपीएफ, एन. ई. रेलवे, को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की हैं. सिविल पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का मानना है कि रात के अंधेरे में कोई इस तरह के पोस्टर रेलवे परिसर और रेलवे की इमारतों में चिपका सकता है, तो किसी दिन आतंकवादी भी यहां घुसकर बम लगा सकते हैं और आरपीएफ की सीआईबी यूनिट सोती रह जाएगी. सिविल पुलिस द्वारा महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को लिखे गए उक्त पत्र की प्रति 'रेलवे समाचार' के पास सुरक्षित है.

कई आरपीएफ कर्मियों का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अधिक दोषी कांस्टेबल सी. के. सिंह ही हैं, क्योंकि ट्रेनर और फोर्स के सिपाही होते हुए भी उन्होंने फोर्स के अनुशासन को भंग किया है. इन आरपीएफ कर्मियों का कहना है कि जब प्रशिक्षण केंद्र में दोनों ट्रेनर ही सैकड़ों प्रशिक्षुओं के समक्ष फोर्स के तमाम अनुशासन को तोड़ते हुए आपस में गाली-गलौज और पत्थरबाजी करते हैं, तब प्रशिक्षुओं को यह कौन सा अनुशासन सिखा रहे हैं? ऐसे में उनका कहना है कि इन दोनों ट्रेनरों का तबादला अविलंब पूर्वोत्तर रेलवे से बाहर किया जाना चाहिए. इसके अलावा प्राप्त अंदरूनी जानकारी के अनुसार यह कांस्टेबल सी. के. सिंह वही हैं, जिनको एक वर्तमान चार्जशीटेड सीएससी का बहुत करीबी होने का दर्जा प्राप्त है? बताते हैं कि उक्त सीएससी की पूर्वोत्तर रेलवे में पोस्टिंग न हो पाने और हाल ही में सेवानिवृत्त पूर्व सीएससी द्वारा उनके मेडिकली डिकैटेगराइज होने के मनसूबे पर पानी फेर दिए जाने से वह अत्यंत बौखलाए हुए हैं. सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके लिए वह सीएससी कार्यालय में कार्यरत एक लाला बिरादरी के मिनिस्टीरियल स्टाफ को जिम्मेदार मानते हैं. इसीलिए उन्होंने पूरी लाला बिरादरी को गालियां दी हैं और तत्संबंधी पम्फलेट भी उन्होंने ही चस्पा करवाए हैं? इस पूरे प्रकरण में आरपीएफ एसोसिएशन के स्थानीय पदाधिकारियों की चुप्पी सभी आरपीएफ कर्मियों को बुरी तरह खल रही है.

दुनिया के किसी भी देश में सफल नहीं हो पाया रेलवे का निजीकरण -शिवगोपाल मिश्रा

बीकानेर : ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे का निजीकरण होने पर इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी. उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अब तक रेलवे का निजीकरण सफल नहीं हो पाया है. यह स्थिति ब्रिटेन, स्वीडन सहित विश्व के अन्य देशों में पहले ही देखी जा चुकी है, जहां रेलवे को निजी हाथों में सौंपा गया है. कामरेड मिश्रा ने यहां उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे. उन्होंने पत्रकारों बातचीत करते हुए कहा कि डॉ. बिबेक देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट में रेलवे को साफ तौर पर निजी हाथों में सौंपे जाने की अनुशंसा की गई है.

उन्होंने कहा कि देबरॉय समिति की रिपोर्ट का जब विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि इसमें दिए गए सुझाव एवं सिफारिशे न सिर्फ भारतीय रेल के निजीकरण का रास्ता खोल रही हैं, बल्कि यह रेलवे बोर्ड तथा भारतीय रेल की सशक्त आंतरिक संरचना को ध्वस्त कर रेल मंत्रालय को धीरे-धीरे समाप्त करने की

एआईआरएफ के महामंत्री कॉ. शिवगोपाल मिश्रा और उ.प.रे. मजदूर यूनियन के महामंत्री माथुर

योजना का प्रारुप है. कॉम. मिश्रा ने कहा कि इससे रेलवे की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा और यात्रियों पर भी भारी बोझ पडेगा. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेलवे के संचालन हेतु अलग-अलग कंपनियों को व्यवस्थाएं सौंपी जाएंगी, आपसी तालमेल के अभाव में अहित केवल रेलवे और इसमें यात्रा करने वाले आम लोगों का होगा.

कॉम. मिश्रा ने कहा कि जून के तीसरे हफ्ते तक इस समिति की अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है. परंतु इसकी अंतिम रिपोर्ट में भी यदि यही तथ्य सामने आते हैं, तो एआईआरएफ और इससे सम्बद्ध सभी जोनल संगठनों द्वारा 30 जून को काला दिवस मनाया जाएगा. फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है, तो चरणबद्ध आंदोलन चलाकर सरकार के खिलाफ जनआंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि रेलवे से जुडे सभी संगठन इस आन्दोलन में उनके साथ हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 10 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें रेवे में खाली पड़े करीब तीन लाख पदों पर नियुक्ति करने, 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन में शामिल करने, अनुकंपा आधार पर रेलकर्मियों के बच्चों को रेलवे में नौकरी देने, श्रम कानूनों में मालिकों के आधार पर बदलाव नहीं करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इन मांगों को नहीं मानने की स्थिति में 23 नवंबर से रेलवे के सभी 13.35 लाख रेल कर्मचारी एवं अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे.

भारतीय रेल देश के परिवहन की रीढ़ है -राजीव मिश्र...

पेज 2 से आगे... जागरूक करने हेतु विभिन्न स्तर से प्रचार किया जा रहा है.

इसके पूर्व, महाप्रबंधक, वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं अन्य उपस्थित रेलकर्मियों का स्वागत करते हुए मुख्य संरक्षा अधिकारी एन. के. अम्बिकेश ने कहा कि ट्रेन दुर्घटनाओं को हम उनकी गंभीरता के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटते हैं. ट्रेन की आमने-सामने की टक्कर सबसे गंभीर दुर्घटना होती है, जबकि ट्रेन में आग लगने की घटना को दूसरे नम्बर की गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में रखा गया है. मुख्य संरक्षा अधिकारी ने कहा कि ट्रेन में आग लगने में आक्सीजन, सामग्री एवं उष्मा अथवा चिनगारी मुख्य कारक होते हैं. उन्होंने कहा कि विद्युत तारों के शार्ट सर्किट, धूम्रपान करने वालों की लापरवाही, ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग तथा असामाजिक गतिविधियों से ही ट्रेन में प्रायः आग लगती है. इन गतिविधियों की रोकथाम पर कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है. श्री अम्बिकेष ने कहा कि यदि दुर्घटना के मूल कारण को ध्यान में रखा जाए तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. मुख्य संरक्षा अधिकारी ने कहा कि आज की संगोष्ठी में ट्रेनों में आग लगने की घटना पर अंकुश लगाने के तथ्यों पर विचार किया जाएगा, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी.

तकनीकी सत्र में उप मुख्य विद्युत अभियंता/कोचिंग श्रीमती ज्योति कैरो ने 'शार्ट सर्किट के कारण कोचों में आग लगना', उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/रिपेयर विपुल सिंह ने 'कोचों के पीओएच के दौरान अग्नि निवारक उपाय', वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता/समाडि लोकेश सिंह ने 'पैंट्रीकार सहित कोचों में अग्नि निवारक उपाय', उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/यूटीएस धीरेन्द्र कुमार ने 'वाणिज्य विभाग के मामले में अग्नि निवारक उपाय', उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/माल राधेश्याम ने 'विस्फोटक एवं अति ज्वलनशील सामग्रियों की शंटिंग एवं संचालन के समय सावधानी', वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता/डीजल, गोंडा डी. के. खरे ने 'लोको में अग्नि निवारक उपाय', उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल विजय खातरकर ने 'ज्वलनशील सामग्री के अनधिकृत परिवहन की रोकथाम', उप मुख्य विद्युत अभियंता/टीआरडी प्रमोद खत्री ने 'टीआरडी सिस्टम/टीएमसी में अग्नि निवारक उपाय' तथा आमंत्रित प्रतिनिधि मेसर्स आईओसी अमिताभ भारती ने आरडीआई की अग्नि संरक्षा तैयारी पर विस्तृत व्याख्यान दिया. संगोष्ठी का संचालन उप महाप्रबंधक/सामान्य संजय यादव तथा धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/इंजीनियरिंग पी. सी. कंचन ने किया.

गुर्जर आरक्षण आंदोलन : रेल प्रशासन मौन क्यों?

सुरेश त्रिपाठी

सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरियों पर कब्ज़ा जमाकर गुर्जरों के आंदोलन के चलते दिल्ली-मुंबई मार्ग पर पिछले चार-पांच दिनों से लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं. इससे रेलवे को प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो रहा है. मगर रेल प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है. जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से गुर्जरों को खदेड़कर राज्य सरकार ने अपना सड़क यातायात बदस्तूर जारी रखा है, मगर उसने रेल पटरियों से आंदोलनरत गुर्जरों को खदेड़ने की कोई जहमत नहीं उठाई है. जबकि राज्य सरकारें हमेशा कानून-व्यवस्था को राज्य का विषय बताते नहीं थकती हैं. परंतु जब रेलवे पर इस तरह का कोई संकट आता है, तो सभी राज्य सरकारें उसे केंद्र का विषय या उसकी जहमत मानकर कुछ नहीं करती हैं. यहीं पर यह कहना बहुत सामयिक होगा कि यदि आज रेलवे के पास अपनी खुद की सभी कानूनी शक्तियों से संपन्न अपनी पुलिस फोर्स होती, तो ऐसे किसी आंदोलनकारियों की मजाल नहीं हो सकती थी, कि वे रेल पटरियों को अपना घर बनाकर उन पर अपना डेरा डालने की हिम्मत भी जुटा पाते.

पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ियों सहित प्रतिदिन बीसों ट्रेनों के रद्द होने से उसके राजस्व में रोजाना 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है. विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में गुर्जरों को एक प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है. अब वे कुल पचास प्रतिशत में से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने पिछले पांच दिनों से रेल रोको आंदोलन चल रखा है. जिससे सामान्य जनजीवन के साथ ही रेलवे का दैनंदिन संचालन लगभग थम सा गया है, क्योंकि गुर्जर रेल पटरियों पर न सिर्फ बैठे हैं, बल्कि उन्होंने धुप और तेज गर्मी से बचने के लिए रेल पटरियों पर ही झोपड़ी भी बांध ली है और नाच-गाकर समय बिता रहें हैं. जहां एक तरफ गुर्जर नाच-गा रहे हैं, वहीं रेल प्रशासन सोया हुआ है, उसने गुर्जरों को रेल पटरियों से खदेड़ने के ले अब तक अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया है. इस तरह रेलवे राज्य सरकारों के लिए 'गरीब की जोरू' बनकर रह गई है, जिसे जब चाहे तब कोई भी आकर छेड़ सकता है. शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, तो लोग रेल पटरियों पर उतर आते हैं. महंगाई बढ़ गई, तो लोग रेल पटरियों पर ही धरना-मोर्चा करने आ जाते है. यानि राज्य सरकारों की लापरवाहियों और कोताहियों का खामियाजा केंद्र सरकार की संपत्तियों और खासतौर पर रेलवे को भुगतना पड़ता है. फिर भी कानून-व्यवस्था राज्य का विषय होने का रोना हमेशा राज्य सरकारों द्वारा रोया जाता है, जबकि इसे संभाल पाने की उचित और पर्याप्त इच्छाशक्ति का राज्य सरकारों में आज आजादी के 67 साल बाद भी पूरा आभाव बना हुआ है. राजस्थान में गुर्जरों द्वारा रेलवे ट्रैक पर किए जा रहे आंदोलन की वजह से दिल्ली-मुंबई रूट की राजधानी, दूरंतो और प्रीमियम जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं. यात्री ट्रेनों के रद्द होने से रेलवे को उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, जितना बड़ा नुकसान मालगाड़ियों के अनिश्चित समय तक रद्द या एक ही जगह खड़ा रहने से होता है. आरक्षण आंदोलन कर रहे गुर्जरों की वजह से रेलवे को अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. तथापि न तो केंद्र सरकार ने, और न ही राज्य सरकार ने, अब तक गुर्जरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों को संचालित करने के लिए विभिन्न विकल्पों से काम लिया जा रहा है. राजधानी एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस को बदले हुए रूट से चलाया गया है, मगर ये ट्रेनें अपने निश्चित समय से 8 से 10 घंटे की देरी से गंतव्य तक पहुंच रही हैं, जो कि सर्वसामान्य यात्री के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है.

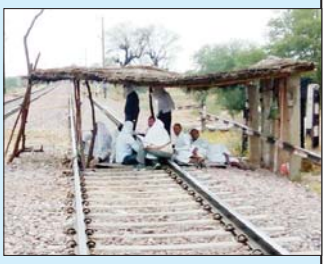

रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं और स्पेशल रीफंड काउंटर भी बनाए हैं. इसके अलावा यात्रियों की मदद करने के लिए कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सहायता बूथ भी बनाए गए हैं. मगर ऐसी अस्थाई व्यवस्था से क्या किसी जरूरतमंद यात्री, जिसकी मां या किसी सगे-सम्बंधी की मौत हो गई हो, को समय पर उसके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है? हालांकि यात्री संगठनों ने गुर्जरों के आंदोलन को समाप्त न करवाने और रेल पटरियों से उन्हें न हटा पाने के लिए सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व की निंदा की है. यह सही है कि राजनीतिक नफे-नुकसान को ध्यान में रखकर कोई भी सरकार किसी भी जाति-वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है. मगर क्या अब सभी मुद्दों/मामलों का निपटारा अदालतों के माध्यम से किया जाना चाहिए? इसलिए अब राज्य सरकारें कानून-व्यवस्था उनका विषय होने की चाहे जितनी दुहाई दें, केंद्र सरकार को यदि रेलवे को पूरे देश में सुचारु रूप से चलाना है, तो रेलवे को उसकी सभी कानूनी शक्तियों से संपन्न पुलिस फोर्स देनी ही होगी, तभी राज्यों के दायरे में होने वाले ऐसे सभी आंदोलनों से निपटा जा सकेगा.

मोदी सरकार का एक साल

रेलवे में काम कम, हलचल ज्यादा

सुरेश त्रिपाठी

मोदी सरकार का एक साल 26 मई को पूरा हो रहा है. बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के पहले साल में रेलवे को राजनीतिक दलदल से निकाल कर यथार्थ के धरातल पर लाने की बहुत जोरशोर से शुरू हुई कोशिशों का कोई खास परिणाम नजर नहीं आया है. भारतीय रेल में इसके लिए पिछले एक साल में समितियों के गठन के रिकॉर्ड कायम किया गया. समिति-दर-समिति बनाए जाने से रेलवे में अपेक्षित सुधारों की गति पर अवरोध लगते रहे और गाड़ियों की लेट-लतीफी तथा लंबी प्रतीक्षा सूची की समस्या से जनता को कोई निजात नहीं मिल पाई. नौकरशाही के कार्य-व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है. सरकार और रेलमंत्री के रेलवे में आमूल-चूल बदलाव की कोशिशों के स्वर रेल संगठनों के तेवरों को देखकर काफी हद तक ठंडे पड़ गए हैं.

रेल मंत्रालय ही मात्र एक ?सा मंत्रालय रहा, जहां मंत्री को प्रदर्शन के आधार पर सिर्फ छह महीनों के अंदर बदल दिया गया. इससे भी रेल मंत्रालय की विश्वसनीयता एक बार फिर भंग हुई. गत वर्ष 27 मई 2014 को रेलवे की कमान संभालने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा को मात्र पांच महीने बाद ही 7 नंवबर 2014 को हटा दिया गया और उनकी जगह टेक्नोक्रेट सुरेश प्रभु को लाया गया. गौड़ा ने मोदी सरकार के पहले रेल बजट से करीब दस दिन पहले जून में रेल यात्री किराए एवं मालभाड़े में वृद्धि कर दी थी, जिससे उनकी तीखी आलोचना हुई. उनका बजट पुरानी लीक पर ही आधारित रहा, जिससे रेलवे में कोई बदलाव नहीं आता देख प्रधानमंत्री ने उन्हें कानून मंत्रालय में भेज दिया.

इधर, सुरेश प्रभु ने जनता पर सीधा बोझ डाले बिना यात्री सुविधाओं और क्षमता वृद्धि के लिए ठोस प्रयास शुरू किए और इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञ राय जुटाने के लिए समितियों के मार्ग का सहारा लिया. उन्होंने कई बड़े फैसले भी किए. रेलवे में ढांचागत सुधारों को लेकर बड़ी पहल की गई और ठेकों तथा नियुक्तियों में पारदर्शिता बरतने के लिए निर्णय प्रक्रिया में सुधार किया गया, मगर सुरेश प्रभु के रेलमंत्री बनने के आज सात महीनों के बाद भी उनका कोई अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आया है.

ठेकों के संबंध में सारे कार्यकारी अधिकार जोनल महाप्रबंधकों एवं मंडल रेल प्रबंधकों को दे दिए गए, जबकि रेलवे बोर्ड को दिशा-निर्देशन एवं नीति-निर्धारण तक ही सीमित किया गया. ई-टेंडर एवं ई-नीलामी की सुविधा शुरू किए जाने की बात कही गई, जो कि रेलवे में काफी पहले शुरू हो चुकी थी. इसी प्रकार से नियुक्तियों में नियमों के अनुपालन को सर्वोपरि बनाने की बात भी हुई, मगर इसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है. भारतीय रेल को 21वीं सदी की आधुनिक रेल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने और प्रक्रियागत सुधारों को लेकर करीब दर्जन भर समितियां बनाई गई हैं, जो एक दूसरे के विपरीत सिफारिशें दे रही हैं.

- पांच महीने में ही रेलमंत्री बदले जाने से रेल मंत्रालय की विश्वसनीयता में कमी आई
- सरकार के रेलवे में आमूल-चूल बदलाव के स्वर रेल संगठनों के तेवर देखकर ठंडे पड़े
- रेलवे में एफडीआई/पीपीपी की बनिस्बत ज्यादा जरूरी हैं आतंरिक एवं प्रशासनिक सुधार
- वर्तमान परिदृश्य में पूरा होने वाला नहीं है रेलवे का सम्पूर्ण उद्धार करने का प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का उद्देश्य

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के पुनर्गठन और निवेश के लिए उच्चाधिकार प्राप्त डा. विबेक देबराय समिति, निविदा प्रक्रिया के संबंध में जोनल एवं मंडल स्तर पर प्रक्रियाओं के निर्धारण के लिए श्रीधरन समिति, केंद्रीय वित्त सचिव मित्तल की अध्यक्षता वाली वित्तीय प्रबंधन समिति, पूर्व सीएजी विनोद राय की समिति तथा मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की अध्यक्षता वाली कायाकल्प परिषद प्रमुख हैं. डॉ. देबराय समिति की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें रेलवे की अनेक सेवाओं के निजीकरण की सिफारिशें की गई हैं, इससे रेलवे के सभी मान्यताप्राप्त संगठन बहुत बुरी तरह से आंदोलित हैं. समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले महीने जून के अंत तक सौंपने का इशारा पीएमओ की तरफ से किया गया है.

देबराय समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें और कायाकल्प परिषद की पहली बैठक में रेलमंत्री के संबोधन एवं रतन टाटा के विचारों में भविष्य में विरोधाभासों के संकेत दिखाई दिए हैं. हालांकि, रेल कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने टाटा के विचारों से काफी हद तक सहमति जताई है, तथापि उन्होंने देबराय समिति से सीधे टकराव की चेतावनी भी दे दी है. मोदी सरकार ने रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाईस्पीड रेल कॉरीडोर आदि परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है. रेलवे में एफडीआई/पीपीपी पर ज्यादा जोर दिए जाने से जयादा जरूरी आतंरिक और प्रशासनिक सुधार होना बहुत आवश्यक है.

मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरीडोर (बुलेट ट्रेन) के लिए जापान की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट अगले महीने आने की संभावना है, जबकि दिल्ली-चेन्नई हाईस्पीड रेल कॉरीडोर का व्यवहार्यता अध्ययन चीन की रेल कंपनी को सौंपा गया है. रेलमंत्री प्रभु ने दक्षिण कोरिया, चीन और चेक गणराज्य के साथ रेलवे में तकनीकी सहयोग के करार भी किए हैं. यात्री सुविधाओं के मामले में कुछ प्रगति अवश्य हुई है.

रेलवे ने इंटरनेट आधारित टिकटिंग सेवाओं में पर्याप्त विस्तार किया है. स्मार्ट फोन के माध्यम से कागज रहित अनारक्षित टिकट पाने की पायलट परियोजना चेन्नई में शुरू की गई है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के आरक्षण पोर्टल की क्षमता में विस्तार किया गया है. लेकिन, आरक्षण के लिए 60 दिन की समय सीमा बढ़ाकर 120 दिन किए जाने से यात्रियों की समस्या कम होने की बजाय बढ़ गई है. प्रतीक्षा सूची और लंबी हो गई है, जिसका फिलहाल कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है.

यात्री सुरक्षा एवं सुविधा के लिए कदम उठाते हुए रेलवे ने दो अलग-अलग हेल्प लाइनें 138 (शिकायत संबंधी) और 182 (सुरक्षा के लिए आपात मदद संबंधी) शुरू की हैं. मुंबई उपनगरीय सेवाओं में महिलाओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है. लोकल गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया. रेल सुरक्षा बल में महिला कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिन्हें ट्रेनों में महिला कोचों में तैनात किया जाएगा.

मगर इस सबसे न तो भारतीय रेल के रोजाना चलने वाले लगभग तीन करो यात्रियों की समस्याओं का कोई बहुत समाधान हो पाया है, और न ही रेलवे की आतंरिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है. जिस तरह केंद्र में नौकरशाही को नरेंद्र मोदी का कोई भय नहीं है, ठीक उसी प्रकार रेलवे में भी नौकरशाहों को रेलमंत्री का कोई भय नहीं है. उधर एक साल बीतते-बीतते नौकरशाही बेलगाम हुई है, तो इधर सिर्फ छह महीनों में ही नौकरशाही रेलमंत्री को अपने शीशे में उतरने में कामयाब हो गई है. जो कि भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण नहीं हैं.

ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे रेलवे बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी काम के बोझ से बुरी तरह लदा हुआ है, हालांकि इनमें से कुछ अपवाद अवश्य हैं. मगर टेबलों पर फाइलों का अंबार लगा लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी काम के बोझ से मरे जा रहे हैं, बल्कि इससे यह अवश्य साबित होता है कि वह काम नहीं कर रहे हैं. यही हाल रेलमंत्री और उनके सेल का भी हो रहा है. इस परिदृश्य में तो भारतीय रेल का कायाकल्प होने से रहा? हां, इससे कुछ लोगों का काफी भला हो सकता है. मगर इससे भारतीय रेल का सम्पूर्ण उद्धार करने का प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का उद्देश्य तो कतई पूरा नहीं होने वाला है.

सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 अतिरिक्त सामान्य डिब्बे जोड़े जाने का निर्णय

अब तक पूरा नहीं किया प्रत्येक ट्रेन में 6 सामान्य कोच जोड़ने का वादा

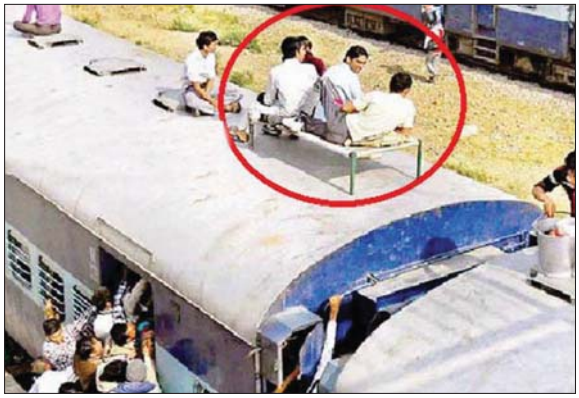

दिल्ली : वैसे तो हर रेल बजट में संसद में यह घोषणा की जाती रही है कि प्रत्येक ट्रेन में कम से कम छह सामान्य डिब्बे जोड़े जाएंगे, मगर अब तक इस घोषणा पर किसी भी सरकार अथवा रेलमंत्री ने अमल नहीं किया है. अब ट्रेनों के सामान्य डिब्बों (जनरल कोच) में यात्रा करने वाली देश की सामान्य जनता को मोदी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. रेलवे ने सभी मेल-एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में दो अतिरिक्त सामान्य डिब्बे लगाने का फैसला किया है. इसकी शुरूआत अत्याधिक भीड़ वाले देश के प्रमुख रेल मार्गों से होगी. इससे करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा होगा.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर क्लास के डिब्बे लगाने की घोषणा की थी. इसके तहत मेल-एक्सप्रेस-सुपरफास्ट, दूरंती, शताब्दी ट्रेनों को पूरी क्षमता से (अधिकतम 26 डिब्बे) चलाने की योजना है, जिससे अधिक से अधिक समान्य यात्रियों को इन ट्रेनों में जगह मिल सके. रेल मंत्रालय ने अब यात्री ट्रेनों में दो सामान्य डिब्बे लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसकी बजट में चर्चा नहीं है. रेल मंत्रालय के इस फैसले से प्रतिदिन सामान्य डिब्बों में सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों को ट्रेनों में जगह नसीब हो सकेगी. रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने एक मुलाकात में पत्रकारों को बताया कि आजादी के बाद रेल यात्रियों की संख्या में 16 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन इस अनुपात में रेल नेटवर्क का विस्तार और क्षमता को नहीं बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि मांग और आपूर्ति के भारी अंतर को कम करने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के उद्देश्य से साढ़े आठ लाख करोड़ से अधिक निवेश करने का फैसला किया गया है.

श्री सिन्हा ने कहा कि देश के प्रमुख रेल मार्गों पर कंजेशन को समाप्त करने के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी रेल लाइन बिछाने का फैसला किया गया है. इससे ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी. ट्रैक पर भारी कंजेशन के चलते रेल बजट में नई ट्रेनें चलाने की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे विशेषकर प्रमुख मार्गों पर भीड़ वाली ट्रेनों में दो अतिरिक्त सामान्य डिब्बे लगाकर जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है.

रेल सफाई अभियान में अब धर्मगुरुओं की मदद लेंगे रेलमंत्री

पणजी : रेलवे में स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रेल धर्मगुरुओं की मदद लेने पर विचार कर रहा है. रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने गोवा में एक समारोह में कहा कि उनका मंत्रालय 'स्वच्छ रेल अभियान' में धर्मगुरुओं को शामिल करने पर विचार कर रहा है. गोवा में आयोजित सूचना तकनीक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेलमंत्री श्री प्रभु ने कहा कि हम एक दिन में स्वच्छ रेल या स्वच्छ भारत नहीं बना सकते हैं. हर यात्री का कर्तव्य रेलवे स्टेशन को साफ रखना है, लेकिन चूंकि लोग यह काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें ही इस काम को अंजाम देना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय सभी धर्म के धर्मगुरुओं को इस अभियान से जोड़ने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि स्वच्छ रेल अभियान में धर्मगुरु बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. श्री प्रभु ने कहा कि कल्पना कीजिए धर्मगुरु जब रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को साफ रखने का संदेश भारी संख्या में अपने अनुयायियों को देंगे, तो कैसा प्रतिसाद मिलेगा.

रेलवे बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कौन करेगा?

सुरेश त्रिपाठी

नए वित्त वर्ष के लगभग दो महीने बीतने जा रहे हैं, परंतु इस साल के लिए प्रस्तावित जीएम पैनल को अब तक भी रेलवे बोर्ड फाइनल नहीं कर पाया है. और जब प्रस्तावित जीएम पैनल अब तक फाइनल नहीं हुआ है, तो यह डीओपीटी भी अब तक नहीं भेजा जा सका है. इस दरम्यान मार्च के पहले सप्ताह में जिन पांच जोनल महाप्रबंधकों की पोस्टिंग का प्रस्ताव पीएमओ भेजा गया था, उसका भी अब तक कुछ अता-पता नहीं है. यह है रेलवे बोर्ड का कार्य-निष्पादन?

पूरा रेलवे बोर्ड सिर्फ जोनों की कार्य-निष्पादन समीक्षाएं करने में लगा हुआ है, मगर जब तक जोनों में उनके मुखिया का ही कोई पता नहीं हो, वहां कार्य-निष्पादन कैसा और किस प्रकार चल रहा होगा, इसका अंदाज बखूबी लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे बोर्ड तो जोनल रेलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कर रहा है, जिसे लगभग हमेशा ही अनिर्णय की स्थिति में रहने की आदत पड़ गई है, ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कौन करेगा? अब यह सवाल बड़ी शिद्दत से पूछा जाने लगा है.

इस बीच जिन वरिष्ठ अधिकारियों को दिसंबर-जनवरी में ही महाप्रबंधक बन जाने की उम्मीद थी, वह भी अब बुरी तरह हतोत्साहित होकर अपने कार्य और उत्तरदायित्व के प्रति अनमनस्क हो गए हैं. रेलवे बोर्ड की इस तरह की कार्य-प्रणाली से तो भारतीय रेल का 'कायाकल्प' होने से रहा, बल्कि यदि यही स्थिति आगे भी बनी रहती है, तो वह दिन भी अब दूर नहीं, जब इसके रसातल में जाने की रही-सही कसर भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी. वास्तव में रेलवे बोर्ड के हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहने के कारण ही भारतीय रेल की आज यह दुर्दशा हुई है, कि हर ऐरा-गैरा आजकल इसे खूब नसीहतें पिला रहा है. चौतरफा बड़ी-बड़ी घोषणाओं का वातावरण गूंज रहा है. बड़े-बड़े लोक-लुभावन भाषण दिए जा रहे हैं. परंतु वस्तुस्थिति तो यही है कि केंद्र सरकार के एक साल पूरा होने पर भी वास्तविक धरातल पर कुछ भी उत्साहित करने वाला काम नहीं हुआ है. न तो रेलवे बोर्ड की कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन आया है, और न ही जोनों का कार्य-वातावरण बदला है, और न ही रेलवे में आवश्यकता से बहुत अधिक चुके अधिकारियों की कार्य-प्रणाली में कोई अंतर आया है. ऐसे में यह उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती है कि इस अनुत्साहित वातावरण में भारतीय रेल का कोई 'कायाकल्प' करने में रेलमंत्री सुरेश प्रभु अथवा कॉर्पोरेट दिग्गज रतन टाटा आने वाले समय में सफल हो पाएंगे?

- अभी-भी जीएम पैनल फाइनल होकर रेलवे बोर्ड से डीओपीटी नहीं पहुंचा
- महाप्रबंधक पदों पर नियुक्तियों का अभी-भी कोई अता-पता नहीं
- आरसीएफ और एनएफआर/कंस्ट्रू. के महाप्रबंधक हो गए सेवानिवृत्त

रेलमंत्री सुरेश प्रभु की काबिलियत पर देश में किसी को भी कोई आशंका नहीं है. परंतु यदि वह भी नौकरशाही की तिकड़मों में उलझकर पूर्व रेलमंत्रियों की ही तर्ज पर रेलवे का कामकाज करेंगे, तो एक साल बीतते-बीतते उनकी काबिलियत पर भी लोगों को आशंकित होने की नौबत आ सकती है. इसलिए 'सुने सबकी, करें अपने मन की' वाली कहावत पर अमल करते हुए उन्हें रेलवे की जमीनी हकीकत बदलने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. श्री प्रभु को अपने सलाहकारों में रेलवे के जानकार और इसके नौकरशाहों की अंदरूनी तिकड़मों की काट रखने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए. तभी वह अगले पांच वर्षों में भारतीय रेल के कायाकल्प का अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं.

रेलवे बोर्ड मेंबर्स का विदेश भ्रमण रद्द, पहले गए मेंबर को भी वापस बुलाया गया

22 मई की रात को करीब 11.35 की उड़ान से विदेश भ्रमण पर जाने वाले तीन बोर्ड मेंबर्स का विदेश दौरा रद्द कर दिया गया है. यह निर्णय पीएमओ के निर्देश पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने लिया है. इस पर तत्काल प्रभाव से रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया. ज्ञातव्य है कि 'रेलवे समाचार' द्वारा अपनी वेबसाइट www.rail-samachar.com पर उक्त बोर्ड मेंबर्स के विदेश दौरे के संबंध में 'रेलवे बोर्ड के चार मेंबर विदेश भ्रमण पर, रेलमंत्री करेंगे 100 रेल परियोजनाओं की शुरुआत' शीर्षक से कल ही यह खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका पीएमओ ने संज्ञान लिया और इस संबंध में तत्काल रेलमंत्री को निर्देश जारी किया.

उल्लेखनीय है कि 22 मई को चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ए. के. मितल सहित मेंबर इलेक्ट्रिकल नवीन टंडन और फाइनेंसियल कमिश्नर/रेलवेज श्रीमती राजलक्ष्मी रविकुमार 31 मई तक 10 दिन के पूर्व निर्धारित चीन और जापान के दौरे पर जाने वाले थे. जबकि 21 मई की रात को मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार 30 मई तक के विदेश दौरे पर रवाना हो गए, मगर उनको भी तत्काल वापस आने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी रेलवे बोर्ड स्थित हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने दी है. रेलवे बोर्ड के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके इस दौरे पर ऐतराज जताया था. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे समय में जब सरकार का एक साल पूरा होने पर रेलवे द्वारा 26 मई से 9 जून तक 'रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा' मनाया जाने वाला है और इसी दरम्यान रेलमंत्री द्वारा 100 नई रेल परियोजनाओं की शुरुआत की जानी है, तब रेलमंत्री के साथ रहने के बजाय लगभग सभी बोर्ड मेंबर्स का देश से बाहर रहना अत्यंत शर्मनाक और शिष्टाचार के विरुद्ध था. उन्होंने इस बात पर भी काफी आश्चर्य व्यक्त किया है कि ऐसे समय में बोर्ड मेंबर्स को विदेश दौरे पर जाने की अनुमति ही कैसे दी गई, जब कि यह पहले से ही निर्धारित था कि सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाने वाला है?

- 'रेलवे समाचार' की खबर का हुआ असर, काम पर लगाए गए सभी बोर्ड मेंबर
- एक दिन पहले विदेश गए मेंबर स्टाफ को भी तत्काल वापस आने का निर्देश दिया गया

पीएमओ की पहल पर रेलमंत्री द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय पर बोर्ड के इन वरिष्ठ अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि रेलमंत्री के इस निर्णय के गहरे निहितार्थ हैं और अन्य अधिकारियों में उनके भी इस निर्णय का काफी गहरा संदेश जाएगा. उनका यह भी कहना है कि वह मानते हैं कि उक्त सभी बोर्ड मेंबर विदेश में घूमने नहीं, बल्कि अधिकारिक ड्यूटी पर जा रहे थे, मगर उनके जाने का समय सही नहीं था, क्योंकि ऐसे समय में उनका रेलमंत्री के साथ जरूरी था, क्योंकि उनके नहीं रहने का बहुत गलत संदेश रेलकर्मियों और देश की जनता में जा सकता था.

पटना स्थित दीघा-सोनपुर और मुंगेर के रेलवे पुलों के उद्घाटन की तैयारी

पटना : मोदी सरकार के एक साल पूरा होने की खुशी में रेल मंत्रालय 30 जून को गंगा पर दो रेलवे पुलों का उद्घाटन करने की तैयारी में है. इनमें पटना का दीघा-सोनपुर रेलवे पुल और मुंगेर का रेलवे पुल शामिल है. इसके अलावा भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से मोकामा में गंगा पर तीसरे सड़क-सह-रेल पुल के निर्माण का फैसला किया गया है. जमीन पर अतिक्रमण के चलते लम्बे समय से उक्त दोनों बड़े रेलवे पुलों का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था, जो अब पूरा हो चुका है और इन पर परीक्षण के तौर पर मोटर ट्राली का संचालन किया जा रहा है. हालांकि राज्य सरकार और रेल अधिकारियों में समन्वय की कमी और भ्रष्टाचार के कारण इन दोनों महत्वपूर्ण रेल पुलों की निर्माण लागत काफी बढ़ गई है.

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के अनुसार सरकार ने एक साल पहले इन पुलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्णय किया था. उन्होंने कहा कि इनके पूरा होने के साथ ही क्षेत्र के लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी. श्री सिन्हा ने बताया कि भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोकामा में तीसरे रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया है. श्री सिन्हा ने गोरखपुर-लखनऊ लाइन के विद्युतीकरण का काम तीन महीने में पूरा हो जाने की भी उम्मीद जताई है. इस बीच मुगलसराय-इलाहाबाद के बीच तीसरी लाइन को भी रेल मंत्रालय ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

श्री सिन्हा के अनुसार एक वर्ष में सरकार ने रेलवे में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जिस राज्य का रेलमंत्री उसी राज्य की रेल की परंपरा को खत्म कर दिया है. अब अगली चुनौती रेल नेटवर्क का विस्तार करने की है, क्योंकि आजादी के बाद यात्रियों की संख्या में 16-17 गुना, जबकि माल ढुलाई की मांग 7-8 गुना बढ़ोत्तरी हुई है. इसके मुकाबले रेलवे का नेटवर्क केवल सवा दो गुना ही बढ़ा है. इस तरह यातायात और नेटवर्क के बीच भारी अंतर पैदा हो गया है.

रेल राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 सालों में रेलवे के मुकाबले सड़क क्षेत्र में छह गुना अधिक निवेश हुआ है. उन्होंने कहा कि अब हमने रेलवे की 30 शीर्ष परियोजनाओं की समय-सीमा तय कर दी है, जबकि 77 अन्य परियोजनाओं की समय-सीमा तय की जाने वाली है. इसके लिए रेलवे में इस साल एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 492 रेल खंडों पर 100 प्रतिशत से ज्यादा, जबकि 260 रेल खंडों में 80-100 प्रतिशत के बीच रेल यातायात है. इन पर यातायात सुगम बनाने के लिए 8,686 करोड़ की लागत से 7,000 किमी. रेल लाइनों के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण का निर्णय किया गया है.

जीएम/द.प.रे. पी. के. सक्सेना ने जारी की संरक्षा पत्रिका 'जागृति'

हुबली : दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पी. के. सक्सेना ने यहां 25 मई को कांफ्रेंस हॉल में एक बैठक के दौरान संरक्षा सम्बंधी कामकाज की समीक्षा की. उन्होंने इस मौके पर द.प.रे. के संरक्षा पत्रिका 'जागृति' का विमोचन भी किया. इस अवसर पर उनके साथ मुख्य संरक्षा अधिकारी विक्रांत कालरा, मुख्य परिचालन प्रबंधक पी. गणेश्वर राव, मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता एम. एलावारासन, उम-मुख्य संरक्षा अधिकारी, ट्रैफिक के. आर. परातें सहित अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने कहा कि रेलवे के दैनंदिन संरक्षा कामकाज की विस्तृत जानकारी देने वाली यह पत्रिका पढ़कर रेलकर्मी रेलवे की संरक्षा बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें प्रकशित संरक्षा नियमवाली का पालन करते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन में संरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है. श्री सक्सेना ने कहा कि पत्रिका में कुछ चुनिंदा रेल दुर्घटनाओं का गहरा विश्लेषण, सतर्कता सलाह, सुरक्षात्मक दिशा-निर्देश, नियमावली में नए संशोधन, आरयूबी/सबवे निर्माण के दिशा-निर्देश 'जागृति' के इस नए अंक में शामिल किए हैं.

महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने संरक्षा संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि 'जागृति' के रूप में उन्होंने सभी रेलकर्मियों और अधिकारियों के लिए एक अत्यंत उपयोगी त्रैमासिक सामग्री प्रस्तुत की है. इस मौके पर सहायक संरक्षा अधिकारी, इंजीनियरिंग एम. देवप्रसाद और सहायक संरक्षा अधिकारी, सिग्नल एस. एम. मलगी और भी उपस्थित थे.

फोटो परिचय : संरक्षा बैठक के दौरान सरक्षा संगठन की संरक्षा पत्रिका 'जागृति' का विमोचन करते हुए द.प.रे. के महाप्रबंधक श्री पी. के. सक्सेना. उनके साथ हैं मुख्य संरक्षा अधिकारी विक्रांत कालरा, मुख्य परिचालन प्रबंधक पी. गणेश्वर राव, मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता एम. एलावारासन, उम-मुख्य संरक्षा अधिकारी, ट्रैफिक के. आर. परातें, सहायक संरक्षा अधिकारी, सिग्नल एस. एम. मलगी और सहायक संरक्षा अधिकारी, इंजीनियरिंग एम. देवप्रसाद.

रेल राज्यमंत्री ने किया पेरिशेबल कार्गो केन्द्र का शिलान्यास

गोरखपुर : गाजीपुर क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए गाजीपुर घाट रेलवे हाल्ट स्टेशन पर पेरिशेबल कार्गो केन्द्र का शिलान्यास रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने 25 मई को किया. इस केन्द्र का निर्माण भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कांकोर) द्वारा किया जाएगा, जो नवम्बर, 2015 तक बन कर तैयार होगा. इसके पूर्व श्री सिन्हा गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में वाई-फाई सुविधा एवं उन्नत यात्री सुविधाओं का भी शुभारम्भ किया. इन दोनों समारोहों में डीजल रेल कारखाना, वाराणसी एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. हरित, कांकोर के प्रबंध निदेषक अनिल कुमार गुप्ता सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे. गाजीपुर जनपद में फल एवं सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, मटर, मिर्च तथा फलों में आम, केला, आंवला, अमरूद आदि को संरक्षित रखने के लिए किसानों की सुविधा हेतु इस कार्गो सेन्टर की स्थापना की जा रही है. उनके उत्पादों में वृद्धि और बाजार से जुड़ाव के जरिए किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यक योजना में सहभागी बनने हेतु आईटीसी लिमिटेड ने अपनी सहमति दी है. किसानों को उच्च पैदावार वाला आलू बीज का आयात इजरायल से किया गया है. केला टिसू कल्चर, जिसमें जी-9 किस्म द्वारा 35 किग्रा. प्रति पौधे तक की उच्च पैदावार प्राप्त की जा सकेगी. किसानों के ज्ञान को बढ़ाने तथा सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मानकों के अनुरूप खेती करने तथा स्थानीय किसानों की परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ालने में आईटीसी ई-चैपाल का भी प्रयोग करेगी. यह संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलें तथा उनके फल और सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सके. 'किसान विजन योजना' के अन्तर्गत निर्मित होने वाले इस पेरिशेबल कार्गो केन्द्र के निर्माण हेतु पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है. 100 मीट्रिक टन के 4 केन्द्र चैम्बर्स में निर्मित होने वाले इस कार्गो केन्द्र में फल एवं सब्जियों को संरक्षित कर उसे ट्रेनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजकर किसान बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे. गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर उन्नत यात्री सुख-सुविधा के अन्तर्गत वाई-फाई सुविधा, पीने के स्वच्छ पानी हेतु आरओ प्लान्ट एवं बैट्री चालित कार्ट का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ रेलयात्रियों को मिलेगा.

'रेलयात्री पखवाड़े' के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारियां

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ए. सी. लाठे ने दिया सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश

गोरखपुर : रेलमंत्री सुरेश प्रभु की पहल पर सभी जोनल रेलों पर 26 मई से 9 जून तक 'रेल यात्री पखवाड़ा' मनाया जा रहा है. इस संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों हेतु मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ए. सी. लाठे की अध्यक्षता में यहां एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप महाप्रबंधक/सामान्य संजय यादव, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी आलोक कुमार सिंह सहित सतर्कता, परिचालन, कार्मिक, विद्युत, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सिगनल, लेखा, यांत्रिक एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री लाठे ने कहा कि महाप्रबंधक राजीव मिश्र के निर्देशानुसार रेल यात्री पखवाड़े के दौरान यात्रियों को स्टेशन परिसर में आने पर उन्हें विशेष आभास हो, इसलिये स्वच्छता के स्तर को उच्चस्तरीय बनाया जाए और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही यात्री सुख-सुविधाओं से उन्हें व्यापक रूप से अवगत कराया जाए.

ग्रीष्मकाल में यात्रा के दौरान गाड़ियों में पानी की उपलब्धता एवं पंखों के चलने को सुनिच्चित किया जाए. महत्वपूर्ण गाड़ियों में स्थाई रूप से कोच बढ़ाए जाएंगे. गोरखपुर एवं लखनऊ स्टेशनों पर विश्रामालयों का उन्नयन किया जाएगा. श्री लाठे ने कहा कि यात्री पखवाड़े के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर चिकित्सा चेकअप कैम्प लगाए जाएंगे और इस दौरान सभी चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं उपकरण समय से उपलब्ध रहेंगे. पैंट्रीकार एवं स्टेशनों पर स्थित खानपान स्टालों में उपलब्ध खाद्य एवं पेय सामग्रियों की निरन्तर जांच की जाएगी, और खानपान की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे की पहली आईएसओ प्रमाण-पत्र धारी लांड्री

गोरखपुर : रेल यात्रियों को साफ-सुथरा बेड रोल उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पर मंडुवाडीह, गोरखपुर, लखनऊ तथा काठगोदाम में कुल चार मेकेनाइज्ड लांड्रियां खोली गई हैं. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे राजीव मिश्र की पहल पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित मैकेनाइज्ड लांड्री, लिनेन केयर सेंटर का मेसर्स वेक्सिल बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा आईएसओ 14001: 2004 हेतु परीक्षण किया गया. इससे भारतीय रेल पर पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर स्थित यह पहली आईएसओ प्रमाण पत्र धारी लांड्री बन गई है. यह पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गर्व की बात है कि लिनेन केयर सेंटर, गोरखपुर को पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम आईएसओ सर्टिफाइड लांड्री और भारतीय रेल की प्रथम आईएसओ 14001: 2004 सर्टिफिकेट अर्हता वाली मैकेनाइज्ड लांड्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है.

एनएफआईआर ने देबरॉय समिति की रिपोर्ट...

पेज 1 से आगे... एनएफआईआर के महामंत्री डॉ. राघवैया ने कहा कि देबरॉय समिति ने पूर्व की केंद्र सरकारों द्वारा रेलवे में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करने और जानबूझकर 10-12 साल तक इसके यात्री किराए नहीं बढ़ाने की स्थितियों को अनदेखा किया है, जिसकी वजह से वास्तव में रेलवे की आर्थिक दुर्गति हुई है. समिति को लिखे अपने इस लम्बे पत्र में इसके उदाहरण स्वरूप डॉ. राघवैया ने कहा है कि जब पिछले एक रेल बजट में रेल किराए बढ़ाने की घोषणा की गई थी और किराए बढ़ाकर भी वापस ले लिए गए थे, तब रेलवे को 7,000 करोड़ रुपए के भारी राजस्व का नुकसान हुआ था. उन्होंने कहा कि निवेश की कमी के लिए संस्था (रेलवे) नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जिम्मेदार रही है.

एनएफआईआर के अनुसार यह कतई उचित नहीं होगा कि बिना आवश्यक ढ़ांचे का निर्माण किए ही निजी और विदेशी निवेशकों को वर्तमान ढ़ांचे के दोहन की अनुमति दे दी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टी के लिए रेलवे के विकास और ट्रेनों की गति बढ़ाने के राजनीतिक वादे की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, मगर यह मजबूरी लाखों रेल कर्मचारियों के भविष्य को बरबाद करके तो कतई पूरी नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए कोई नया रोड-मैप बनाए जाने का उत्साह तो ठीक है, मगर देबरॉय समिति ने तो भारतीय रेल के लिए तमाम निजीकरण और ऊल-जलूल सिफारिशें करने से पहले यूरोपियन रेलों तक का अध्ययन करना उचित नहीं समझा, जहां ऐसी ही कोशिशों के चलते रेल व्यवस्था पूरी तरह बरबाद हो गई और उसका खामियाजा आज भी ब्रिटेन सरकार को ब्रिटिश रेलवे को चलाने वाली कथित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को भारी सब्सिडी देकर चुकाना पड़ रहा है, जो कि कहने को आज भी 'सरकारी मालिकाना हक' वाली ही है. डॉ. राघवैया ने अपने पत्र में ब्रिटिश रेलवे के निजीकरण के प्रयोग के दुष्परिणामों पर अंग्रेज लेखक और रेलवे के प्रसिद्ध इतिहासकार क्रिस्चियन वोल्मर के लिखित अनुभवों को उदधृत करते हुए कहा है कि 'निजीकरण और विखंडन ने (ब्रिटिश) रेलवे को बेकार कर दिया है, जबकि ऐसा यात्रियों की चिंता किए बिना विचारधारा और वित्तीय कारणों से किया गया था. डॉ. राघवैया का कहना है कि यह सतही और अनर्थकारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए देबरॉय समिति ने या तो जल्दबाजी में रेलवे बोर्ड से तथ्य (इनपुट्स) मंगा लिए थे, अथवा रेलवे बोर्ड ने बिना देखे-समझे ही अपनी इच्छा के मुताबिक यह इनपुट्स समिति को सौंपे थे. उनका कहना है कि समिति ने अपना कोई दिमाग लगाए बगैर ही यह रिपोर्ट तैयार की है और अब इस पर अनावश्यक स्पष्टीकरण देते हुए समिति के अध्यक्ष द्वारा 'प्राइवेटाइजेशन' की जगह 'पार्टिसिपेशन' की बात कही जा रही है. उदाहरण के लिए डॉ. राघवैया का कहना है कि देबरॉय समिति की रिपोर्ट के पेज नं. 66 पर दिए गए एक टेबल में 'परभणी' को दक्षिण मध्य रेलवे का एक और मंडल दर्शाया गया है, जबकि भारतीय रेल में इस नाम का कोई मंडल ही नहीं है. दक्षिण मध्य रेलवे में सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल और नांदेड़ नामक सिर्फ छह मंडल ही हैं.

देबरॉय समिति द्वारा रेलवे के क्षेत्र में नए खिलाड़ियों को मौका देकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिए जाने की छद्म सिफारिश का पर्दाफाश करते हुए डॉ. राघवैया ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है. उनका कहना है कि 1990 से बड़े पैमाने पर हुए गेज कन्वर्शन के कारण भारतीय रेल ने अपने नेटवर्क में ज्यादा विस्तार न कर पाते हुए भी बढ़े हुए फ्रेट एवं पैसेंजर वॉल्यूम का परिवहन सफलतापूर्वक किया है. उन्होंने कहा कि देबरॉय समिति की रिपोर्ट में कई जगहों पर भारी गड़बड़ी और विसंगतियां हैं. उदाहरण के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ बहुत विशेष और असंगत एवं गैर-महत्वपूर्ण सेवाओं (नॉन-कोर सेग्मेंट्स) को छोड़कर वह भारतीय रेल के निजीकरण की सिफारिश नहीं कर रही है. परंतु इसके तुरंत बाद समिति यह भी कहती है कि 'प्राइवेटाइजेशन' किया जाना चाहिए, मगर यह 'लिब्रलाइजेशन' के साथ हो.' जबकि समिति वहीं पर रोलिंग स्टॉक के उत्पादन को तर्कसंगत बनाए जाने के बारे में जानबूझकर कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं करती है, जो कि भारतीय रेल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक सेग्मेंट है. उन्होंने कहा कि वास्तव में देबरॉय समिति की इस रिपोर्ट में न सिर्फ ऐसी अन्य बहुत सी आधारभूत विसंगतियां हैं, बल्कि यह पूरी रिपोर्ट ही अत्यंत विडम्बनापूर्ण है. एनएफआईआर के महामंत्री डॉ. राघवैया ने ऐसे समय में जब भारतीय रेल पर कुल करीब 1.86 लाख करोड़ की रेल परियोजनाएं अटकी पड़ी हुई हैं, तब सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर अमल किए जाने के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध सरकार को आगाह किया है. उनका कहना है कि ऐसी कोई भी 'रिस्ट्रक्चरिंग' की कसरत नहीं की जा सकती है, जो कि भविष्य की जरूरतों पर बिना कोई गंभीर अध्ययन किए ही वर्तमान व्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो. 'रेलवे रेगुलेटरी बॉडी' के गठन की देबरॉय समिति द्वारा की गई सिफारिश की कड़ी आलोचना करते हुए डॉ. राघवैया ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी 'रेगुलेटरी' की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारतीय रेल की स्वतःस्फूर्त अंदरूनी प्रक्रिया को 'रूटिंग एंड रेटिंग सिस्टम' के तहत पुनर्जीवित किए जाने की जरूरत है. इसी प्रकार यदि भारतीय रेल को पेंशनरी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए, तो स्टाफ लागत भी लगभग न्यूनतन रह जाएगी. डॉ. राघवैया का कहना है कि विश्व की अन्य रेलों की तरह ही देबरॉय समिति भी समस्या की जड़ में पहुंचने में नाकाम रही है. उनका कहना है कि किसी एक लाइन पर ढोए जा रहे फ्रेट के वॉल्यूम और उक्त लाइन पर पूर्व निर्धारित फिक्स्ड फ्रेट रेट के बीच कोई संबंध नहीं होता है. इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि देबरॉय समिति ने रेलवे के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देने के बजाय इसकी मेडिकल, स्कूल और आरपीएफ जैसी कुछ आवश्यक गतिविधियों को रेलवे से अलग किए जाने की गलत धारणा बनाई है. जबकि रेलवे की यह सभी मुख्यधारा की गतिविधियां हैं. उनका कहना है कि रेलवे की अपनी फोर्स (आरपीएफ) की गैर-मौजूदगी में रेल संपत्तियों की लूट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. बल्कि डॉ. राघवैया का तो यहां तक कहना है कि आरपीएफ को सम्पूर्ण आईपीसी और सीआरपीसी के अधिकार देकर सिविल पुलिस के समकक्ष फोर्स बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है. जबकि भारतीय रेल की लोकोमोटिव एवं कोचों के मेंटेनेंस में आत्म-निर्भरता की सराहना करने के बजाय देबरॉय समिति ने इसके लिए बाहरी एजेंसियों को लाए जाने की सिफारिश की है, जिससे सर्विस की गुणवत्ता बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी.

रेल उपभोक्ता पखवाड़ा - मोदी सरकार का एक और अभियान...

पेज 1 से आगे... समूचा रेलतंत्र भारतीय रेल के इतिहास में अपनी तरह के इस पहले एवं विशाल कार्यक्रम के लिए कमर कस ली है.

रेलमात्री श्री प्रभु के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साल पहले सरकार बनने के बाद कहा था कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और एक साल बाद 25 मई को उन्होंने मथुरा में प. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नंगला चंद्रभान में आयोजित एक रैली में इसी बात को दोहराया है. रेलमंत्री के अनुसार रेलवे ने 26 मई से 9 जून तक रेल यात्री पखवाड़ा इसी के अनुरूप मनाने का फैसला किया है.

इन 15 दिनों में रेलवे बोर्ड के 80 अधिकारियों सहित सभी जोनल एवं मंडल कार्यालयों में तैनात बड़े अधिकारी करीब आठ हजार स्टेशनों पर जाएंगे और वहां पर यात्रियों, कर्मचारियों एवं अन्य पक्षों से बातचीत करेंगे. वे स्टेशन पर रेल बजट की घोषणाओं तथा वहां दिक्कतों एवं सुविधाओं को लेकर करीब 50 बिन्दुओं पर अध्ययन करेंगे.

इस दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों एवं मंडलों के स्तर पर करीब डेढ़ सौ रेल परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा और तमाम नए करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इनमें राज्य सरकारों के साथ रेलवे के संयुक्त विशेष प्रयोजन उपक्रमों की स्थापना के करार शामिल हैं.

यात्रियों को जागरूक करेंगे अधिकारी

इस दौरान रेल अधिकारी और कर्मचारी अभियान से संबंधित टोपी पहनकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को स्वच्छता तथा सुरक्षा को लेकर जागरूक करेंगे. इससे रेलवे परिसरों और ट्रेनों को साफ रखने तथा रेल हादसों में कमी लाने में मदद मिलेगी. यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं या परेशानियों के समाधान के लिए यात्रियों से सुझाव लेकर रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी.

26 मई से 9 जून तक चलने वाले इस अभियान में रेलवे के जोनल महाप्रबंधक, मंडल प्रबंधक, स्टेशन प्रबंधक से लेकर सभी छोटे-बड़े अधिकारी शामिल होंगे. अभियान में कर्मचारियों के साथ रेलवे के सभी अधिकारी भी शामिल होंगे. सभी मिलकर यात्रियों को स्टेशन परिसर, रेलवे पटरी और ट्रेन को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जागरूक करेंगे. उन्हें स्वच्छता के लिए रेल प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी जाएगी. इसी तरह से दुर्घटनाओं को टालने के लिए भी यात्रियों को जागरूक किया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि बिना कर्मचारी वाले रेलवे फाटक पर अक्सर हादसे होते रहते हैं. इसलिए यात्रियों को इस तरह के फाटक पर विशेष सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसी तरह अवैध रूप से रेलवे पटरी पार करते हुए भी लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. पटरी पार करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है. यात्रियों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे वह ऐसी गलती न करें. इसके साथ ही ट्रेन के पायदान पर खड़ा होकर यात्रा करना, चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना भी खतरनाक है.

ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में चलने से आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं. इसलिए जागरूकता अभियान के दौरान यात्रियों को इस बारे में जागरूक करना जरूरी है. मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में रेल के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी. इस दौरान रेल अधिकारी प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे और ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे. यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी.

देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट....

पेज 1 से आगे... तोड़ने वाला एक दस्तावेज है, जो कि पूरे देश को अपने लगभग 65 हजार रूट किमी. नेटवर्क से एक सूत्र में पिरोते हुए एकजुट कर रही है.

स्थाई समिति के सदस्यों का मानना था कि रेलवे ही इस देश की एकमात्र ऐसी सस्ती, सुलभ और सुरक्षित यातायात व्यवस्था है, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए दूर-दूर तक आ-जा सकता है. इस यातायात व्यवस्था में ही विद्यार्थी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर यात्रा कर सकते हैं. दैनिक यात्री भी अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए इसमें यात्रा करते हैं. यदि डॉ. देबरॉय की रिपोर्ट को मान लिया जाता है तो इन सभी लोगों को न सिर्फ अपनी रोजी-रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इन सबका रोजाना का घरेलू बजट भी बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगा.

एआईआरएफ की स्थाई समिति के सदस्यों का कहना है कि वर्तमान सरकार कॉर्पोरेट घरानों को ट्रेन सेवाएं चलाने और रेल यात्रियों से हवाई टिकटों जैसे रेल किराए वसूलने की अनुमति देकर सिर्फ बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही वर्तमान रेलवे व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही है. डॉ. देबरॉय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनों के रख-रखाव और उनके दैनंदिन संचालन में स्थाई कर्मचारियों की जगह ठेका मजदूरों को रखा जाए. ऐसे में ठेका मजदूर स्थाई रेलवे कर्मचारियों की जगह ले लेंगे, जिनका पहले ही बहुत शोषण हो रहा है.

एआईआरएफ की स्थाई समिति ने डॉ. देबरॉय की अंतरिम रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए रेलवे में रोजाना यात्रा करने वाले करीब तीन करोड़ यात्रियों, दैनिक यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और रेलकर्मियों का आहवान किया है कि वे गरीब विरोधी, सर्वसामान्य आदमी की विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध प्रकट करें और इस सार्वजनिक सरकारी यातायात व्यवस्था को बचाएं. एआईआरएफ की स्थाई समिति ने देश की जनता और खासकर रेलकर्मियों का आहवान करते हुए कहा है कि 23 से 30 जून तक देश भर सभी जगह देबरॉय समिति की अंतरिम रिपोर्ट के खिलाफ धरना, मोर्चा आदि सहित 'कैपेन वीक' मनाया जाएगा और 30 जून को 'काली पट्टी' बांधकर विरोध प्रकट किया जाएगा.

एआईआरएफ की स्थाई समिति के सदस्यों का मानना है कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा सात साल का समय निर्धारित किया गया है. जबकि निजी कंपनियों को गाड़ियां चलाने और अपनी इच्छानुसार मालभाड़ा एवं टिकट किराए वसूलने का त्वरित लक्ष्य तय किया गया है.

डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय रेलवे पुनर्गठन समिति की प्रमुख सिफारिशें-

1. ट्रेन सेवाओं, माल भाड़ा और टिकट दरों की आउटसोर्सिंग तय करने के लिए 'रेलवे रेगुलेटरी ऑफ इंडिया' का गठन.
2. निजी कंपनियों को ट्रेनें चलाने और अपनी इच्छानुसार मालभाड़ा तथा टिकट दरें वसूलने की अनुमति.
3. छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार लोगों, खिलाड़ियों, पत्रकारों और विकलांग लोगों की सभी प्रकार की रियायतों को बंद कर दिया जाना चाहिए.
4. 'इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी' के नाम से रेलवे की सभी उत्पादन इकाईयों और कारखानों को एक निजी कंपनी में बदलने की सिफारिश, जिसे निजी कंपनियों की तरह चलाया जाएगा.
5. कॉन्ट्रैक्टर्स को रेलवे का सभी निर्माण, संचालन और रख-रखाव का काम सौंप दिया जाना चाहिए.
6. सभी रेलवे स्कूलों और रेलवे अस्पतालों को बंद कर दिया जाना चाहिए अथवा इन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए.
7. आरपीएफ की सभी गतिविधियां इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स को सौंप दी जानी चाहिए.
8. रेल कर्मचारियों की संख्या को बहुत कम किया जाना चाहिए.
9. दयाधार और लार्सजेस के तहत रेलकर्मियों के बच्चों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य का तीसरी बार तबादला

मगर पुनः हो रही है तबादला रोकने की तिकड़म

कोलकाता : मेट्रो रेलवे, कोलकाता के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य का तबादला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी के लिए कर दिया गया है. उनका यह तीसरा तबादला है. इसका आदेश रेलवे बोर्ड चिकित्सा निदेशालय द्वारा 6 मई को जारी किया गया था. परंतु आज करीब पंद्रह दिन बाद भी उन्हें उनके पद से मुक्त नहीं किया गया है. पता चला है कि उनका यह तीसरा तबादला सांसद द्वय श्री अजय निषाद और श्री ए. के. सिंह की रेलमंत्री को की गई लिखित शिकायत पर किया गया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले डॉ. भट्टाचार्य अनुचित तरीकों से अपने दो तबादले निरस्त कराने में सफल रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य का यह तबादला आदेश सीधे रेलमंत्री सुरेश प्रभु के कहने पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है. इस आदेश में उनकी जगह मेट्रो रेलवे में डॉ. मिहिर कुमार चौधरी, (सीएमएस/न्यू जलपाईगुड़ी) को पदस्थ किया गया है. रेलवे बोर्ड द्वारा 6 मई को जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले डॉ. मिहिर कुमार चौधरी अपने पद से मुक्त होकर कोलकाता आएंगे और वह डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य को मेट्रो रेलवे से पद मुक्त करेंगे. परंतु आज करीब पंद्रह दिन बाद भी दोनों को ही उनके पदों से मुक्त करके उनकी नई जगहों पर नहीं भेजा गया है. ज्ञातव्य है कि विगत में

दो सांसदों की रेलमंत्री को की गई लिखित शिकायत पर हुआ है डॉ. भट्टाचार्य का यह तबादला

'रेलवे समाचार' ने पूर्व रेलवे के तत्कालीन सीएमडी डॉ. राठौर, डॉ. मिहिर चौधरी और डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य की तिकड़ी सहित कई अन्य डॉक्टरों के अनुचित कार्य-व्यवहार का विस्तृत पर्दाफाश किया था. यही वजह है कि कोलकाता के तमाम रेल कर्मचारी डॉ. मिहिर चौधरी, जिन्होंने करीब डेढ़ साल पहले पश्चिम रेलवे, मुंबई के लिए हुआ अपना तबादला निरस्त करवाकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (सीएमएस/न्यू जलपाईगुड़ी) में करवा लिया था, का भी फिर से कोलकाता आना शुभ नहीं मान रहे हैं. उनका कहना है कि जब से यह बाहर गए हैं, तब से कोलकाता में काफी शांति रही है. बताते हैं कि इस बार भी डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य अपने राजनीतिक आकाओं और यूनियन वालों की मदद से पुनः अपना यह तीसरा तबादला निरस्त कराने की जुगाड़ में लगे हुए हैं. यही वजह है कि अब तक उन्हें मेट्रो रेलवे से पद मुक्त नहीं किया है. ऊल्लेखनीय है कि कोलकाता में सर्वाधिक विवादस्पद और अनुचित कार्य-व्यवहार के लिए जाने जाने वाले डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य मात्र एक या दो साल के लिए ही अब तक अपनी कुल सेवा में कोलकाता से बाहर गए हैं. कोलकाता स्थित पूर्व एवं दक्षिण पूर्व रेलवे के कई डॉक्टरों का कहना है कि यदि इस बार भी डॉ. रुद्रेंदु भट्टाचार्य अपना तबादला निरस्त कराने में सफल हो जाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि वह रेलमंत्री से 'यादा पॉवरफुल हैं. इस बारे में कोई भी सम्बंधित अथॉरिटी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

रेलवे ट्रैक पर आंदोलनों पर

पेज 1 से आगे... यद्यपि परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, तथापि सिगनल, लोको, ट्रैक फेलियर मामलों से निपटने के लिए और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने रेल प्रशासन को निर्देश दिया कि लगभग 25-25 किमी. के जीरो-फेलियर मॉडल सेक्शन बनाए जाएं, जिन्हें बाद में और विस्तार दिया जाए. वर्ष 2014-15 के दौरान उत्तर रेलवे जोन ने 54.90 मिलियन टन का राजस्व लदान दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की 7904.3 करोड़ रुपए की आय से 2.86 प्रतिशत अधिक है. इस कार्य-निष्पादन की सराहना करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि चालू वर्ष के दौरान मालभाड़ा लदान के दिए गए लक्ष्य से 15 प्रतिशत अधिक का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाई जाए. उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के लदान-आदेशों में कमी के मद्देनज़र मालभाड़ा लदान की नई सम्भावनाएँ खोजी जाएं. उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे की कुल प्रारम्भिक आय में 11.01 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वर्ष 2014-15 में राजस्व आय के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय रेलों के मुकाबले तीसरे स्थान पर रहा है. वैगन टर्न अराउंड अथवा एक वैगन के एक लदान के बाद दूसरे लदान के बीच का अंतराल 1.42 दिवस रहा, जबकि भारतीय रेल का सामान्य औसत 5.13 दिवस है. आंकडों की समीक्षा करते हुए रेल राज्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने नए अनुमोदित कार्यों को किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और आशा व्यक्त की कि इन कार्यों के लिए आवंटित निधि का पूर्णतः उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ ही अनुकम्पा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों एवं अन्य कर्मचारी मामलों में भी तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और आशा प्रकट की कि इन मामलों की बेहतर निगरानी के लिए इसे ऑन लाइन किया जायेगा.

निःशक्त रेलकर्मियों के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कार्यशाला का आयोजन

दिल्ली : उत्तर रेलवे द्वारा सोमवार, 25 मई को उ.रे. मुख्यालय, बड़ोदा हाउस में निःशक्त रेलकर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उनके रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी देने सहित इस क्षेत्र में हुए नए अनुसंधानों, महत्वपूर्ण विकास और उपलब्धियों संबंधी विस्तृत जागरूकता पैदा करना था. कार्यशाला की अध्यक्षता उ.रे. के मुख्य कार्मिक अधिकारी आनंद माथुर ने की. इस अवसर पर उ.रे. केंद्रीय अस्पताल स्थित आर्टिफीसियल लिंब सेंटर के प्रबंधक एम. सी. दास और उ.रे. फिजिकली हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता भी उपस्थित थे. इस कार्यशाला में विजुअली इम्पेयर्ड, ओर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड जैसे अन्य निःशक्त रेलकर्मियों ने भी हिस्सा लिया. इस मौके पर सीपीओ श्री माथुर ने शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मियों के लिए एक पत्रिका का भी विमोचन किया. इस पत्रिका में दृष्टिहीन कर्मियों के लिए ब्रेल लिपि में आवश्यक जानकारी का अनुवाद भी किया गया है. इस मौके पर मूक-बधिर कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु सांकेतिक भाषा के जानकार भी उपस्थित थे. इस अवसर पर उपस्थित सभी निःशक्त रेलकर्मियों को उनके लिए रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई. सीपीओ श्री माथुर, जो कि सेंट्रल स्टाफ बेनीफिट फंड समिति के चेयरपर्सन भी हैं, ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो निःशक्त रेलकर्मियों को मोटोराइज्ड व्हील चेयर और अन्य अधिक सुविधाजनक यंत्र स्टाफ बेनिफिट फंड के अतिरिक्त भी मुहैया कराए जाएंगे.

वाणिज्य विभाग, द.प.रे. ने वितरित किया सीसीएम अवार्ड

गाड़ियों की समयबद्धता और सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जाए -विशाल अग्रवाल

हुबली : साठवें रेल सप्ताह के अवसर पर द.प.रे. के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विशाल अग्रवाल ने यहां वाणिज्य विभाग के सराहनीय काम करने वाले वाणिज्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए. इस मौके पर मुख्य परिचालन प्रबंधक पी. गणेश्वर राव, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एफएम जे. नागराजू और मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक एन. श्रीनिवास सहित अन्य सभी वाणिज्य अधिकारी और बड़ी संख्या में वाणिज्य कर्मचारी उपस्थित थे. इस अवसर पर सर्वप्रथम सहायक वाणिज्य प्रबंधक, मुख्यालय एन. राजकुमार ने मुख्य अतिथि सीसीएम सहित सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया.

मुख्य अतिथि के रूप में इस मौके पर उपस्थित वाणिज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री अग्रवाल ने पुरस्कार पाने वाले वाणिज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे. उन्होंने गाड़ियों की समयबद्धता को सुनिश्चित करने और सुचारु संचालन तथा अनावश्यक रुकावटों को टालने पर जोर दिया. उन्होंने पर्यवेक्षकों से कहा कि वे फील्ड स्टाफ को रेल यातायात के महत्व को समझाएं और उन्हें इस बात की जानकारी दें कि यात्री और माल यातायात बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए. उन्होंने वाणिज्य कर्मियों से कहा कि वे स्टेशनों और चलती गाड़ियों में यात्रियों के लिए मुहैया कराई गई सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करवाएं.

सीसीएम श्री अग्रवाल ने इस मौके पर द.प.रे. के मुख्यालय सहित बंगलौर, मैसूर और हुबली तीनों मंडलों के 83 वाणिज्य कर्मियों को वर्ष 2014-15 में उनकी सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र और 2-2 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया. इस मौके पर डिप्टी सीसीएम/पीएस टी. पी. गणेश सहित सभी पुरस्कृत कर्मचारी और तीनों मंडलों एवं मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. सहायक वाणिज्य प्रबंधक/एफएस अरविंद हरले ने सभी उपस्थितों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.,
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.,
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक **सुरेश त्रिपाठी** द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : **उमेश शर्मा** ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : **विजय शंकर** ☎ 094508 80000
- भुसावल : **शेख सत्तार** ☎ 093706 15244
- रतलाम : **मुकेश सिंह** ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : **विजय नायर** ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण, एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई, एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे, एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली, एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल, एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.
किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017